

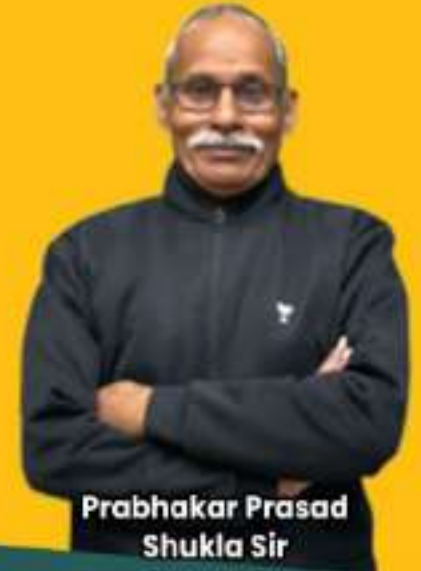


**Specially for RJS Mains**

# निबन्ध रचना राजस्थानी भाषा संवैधानिक मान्यता

25<sup>th</sup> April | 4:45 PM

**LIVE** Linking Laws



**Prabhakar Prasad  
Shukla Sir**

All State Judiciary & Law Exams

Unacademy Goal

Achieve your exam goal

with

**20% off**

on all subscription\*

April 25-28

## Our Running Batch

**Linking Regular Batch 2.0**

Started from 13 April 2022

**APO Linking Batch**

Started from 20 April 2022

**DJS Mains Revision Batch**

**COMING  
SOON**

Use Code : **PPS32** and get 20% off | For More Information **7825860310**

## राजस्थानी भाषा: संविधान की आठवीं अनुसूची में रखने की मांग

“निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।  
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल।।”

भारतेन्दु जी की पंक्तियाँ जब भी कान में गूँजती हैं, दिल में अपनी भाषा के प्रति प्रेम सहजभाव से उत्पन्न हो जाता है। इस आधार पर जब भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और संविधान की आठवीं अनुसूची में रखने की बात चलती है तो मन में हूक उठनी स्वाभाविक हो जाती है कि क्या कारण हैं जिनकी वजह से अभी तक हमारी प्रिय भाषा को गौरवमयी स्थान

प्राप्त नहीं हुआ, जबकि राजस्थानी भाषा की मान्यता की मांग सबसे पहले सन् 1936 में उठी थी। जब देश आज़ाद हुआ तो सन् 1956 में राजस्थान विधानसभा में भी इसको संविधान मान्यता देने की मांग उठी थी, किन्तु परिणाम वही - 'ढाक के तीन पात ।' यह भी देखा गया है कि राजस्थानी भाषा को उचित सम्मान दिलाने हेतु संघर्ष कर रहे तमाम संगठनों और लोगों ने समय-समय पर सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को उठाया है। एक ऐसी भाषा जो देश की आज़ादी के पूर्व राजस्थान, मालवा और उमरकोट (अब पाकिस्तान में) की राजभाषा हुआ करती थी, साहित्य के क्षेत्र जिस डिंगल भाषा ने दुनिया में डंका बजाया था, वही भाषा आज अपने ही राज्य या सूबे में अपना अस्तित्व बचाए रखने और अपनी पहचान कायम रखने के लिए निरन्तर संघर्ष

कर रही है और उसे अभी वांछित सफलता भी प्राप्त नहीं हो पा रही है।

“आभलिया तूं रूप सरूप, बादल बिन बरसे नहीं।

साळा घणां सपूत, भीड़ भाइयों बिना भागे नहीं।।”

अर्थात् आसमान कितना भी खूबसूरत हो, बादल के बिना बारिश नहीं होती और साले कितने भी सपूत हों लेकिन घर में भीड़, घर भरा और खुशहाल तभी लगेगा जब आंगन में अपने भाई खड़ें हों।

ठीक इसी तरह राजस्थान में भी व्यावसायिक रूप से हिन्दी-अंग्रेजी समेत अनेक भाषाएँ कितनी भी समृद्ध दिखाई दे रही हों लेकिन जो अपनत्व और आनन्द की अनुभूति अपनी मायड़ भाषा दे सकती है, वह अन्य भाषा से प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं है।

पश्चिमी राजस्थान और उमरकोट के क्षेत्र में यहाँ के चारण कवियों ने जिस भाषा में साहित्यिक रचना की, उसे डिंगल भाषा कहते

हैं। डिंगल के प्रमुख रचनाकारों में पृथ्वीराज राठौड़, ईसरदासजी, दुरजा जी आढ़ा, सूर्यमल्ल मिश्रण, बांकीदान जी आशिया, करणीदान कविया और बांकीदास प्रमुख हैं।

पूर्वी राजस्थान में राजस्थानी और ब्रज भाषा आपस में मिली हुई दिखाई देती हैं और इस क्षेत्र की जो भी साहित्यिक रचनाएँ जिस भाषा में हुईं उसे पिंगल की संज्ञा दी गई। यहाँ के कवि भाट थे जिन्होंने इसे मायड़ भाषा के बराबर दर्जा दिया है।

स्वतन्त्रता से पूर्व जागीरदारी से रियासत तक, सर्वत्र लेखक और कवियों का सम्मान होता था, सम्मान करने वाले गर्व का अनुभव करते थे, इस तरह हमारी भाषा रोज़गार परक थी। लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् रजवाड़े खत्म क्या हुए, अब तो हमारी

संस्कृति और भाषाओं को भी दरकिनार कर दिया गया है। इन्हें संवैधानिक दर्जा देना तो दूर, तिल-तिल कर खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है।

अपनी लाइली भाषा को यदि समय रहते संवैधानिक मान्यता नहीं दिला सके तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। फिलहाल उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए -

“मायड़ भाषा लाइली, जन-जन कण्ठा हार,  
लाखां-लाखां मोल है, गाओ मंगलाचार।  
वो दिन वेगो आवसी, देय मानता राज,  
पल-पल गास्यां गीतड़ा, दूना होसी काज।।”

## हिन्दी अनुवाद

1936

जब भी राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की बात चलती है, तो अनेक जटिलताओं का जिक्र किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नजर डालें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ-साथ साहित्य अकादमी ने इसे एक अलग भाषा के रूप में मान्यता दे रखी है। राजस्थान के अनेक विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन और अध्यापन भी होता है, प्रश्नपत्र बनते हैं, उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच भी होती है, तो प्रतियोगी परीक्षाएँ क्यों नहीं करवायी जा सकतीं?

मान्यता की जो मांग 1936 में उठी थी, सन् 2003 में पहली बार राजस्थान सरकार ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को भेजा। केन्द्र सरकार ने एस. एस. महापात्रा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट में भोजपुरी के साथ राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए पूरी तरह से पात्र

बताया। सन् 2006 में केन्द्र सरकार ने तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री की सहमति के आधार पर मान्यता का बिल भी बनाया किन्तु आज तक वह संसद में पेश नहीं हो पाया।

सन् 2009 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर से सांसद बने अर्जुनराम मेघवाल ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेनी चाही, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, आज उनके दल की ही सरकार है फिर भी मायड़ भाषा को सही सम्मान अभी तक दिलाने में वे असमर्थ नजर आ रहे हैं। आज अनेक लोग राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए जनजागरण कर रहे हैं।





Judiciary

# Unacademy Goal

Achieve your exam goal with 20% off on all subscription\*

**Hurry! Offer ends on April 28, 2022**

Duration	Plus Regular Price	Plus Offer Price	Iconic Regular Price	Iconic Offer Price
24 Months	<del>₹ 63,250</del>	₹ 50,600	<del>₹ 1,04,650</del>	₹ 83,720
18 Months	<del>₹ 52,367</del>	₹ 42,694	-	-
12 Months	<del>₹ 43,484</del>	₹ 34,788	<del>₹ 64,185</del>	₹ 51,348
6 Months	<del>₹ 31,625</del>	₹ 25,300	<del>₹ 41,975</del>	₹ 33,580
3 Months	<del>₹ 19,766</del>	₹ 15,813	-	-
1 Month	<del>₹ 2,906</del>	₹ 6,325	-	-

All State Judiciary & Law Exams

## Our Running Batch

### Linking Regular Batch 2.0

Started from 13 April 2022

### APO Linking Batch

Started from 20 April 2022

### DJS Mains Revision Batch

COMING SOON

Use Code **LINKING** and get 20% off

For More Information



**7825860310**

# SPECIAL CLASS FEATURES

## Interactive Live Classes



Attend Live Class, participate in Live Chat and get your doubts cleared - all during the class.

## Polls for Learners



Respond to polls for a better understanding of a topic.

## Raise A Hand



Plus Subscribers can Talk with educators in Live Classes and get the doubts resolve in real time.

## Never Miss a Class



Get notified for lessons, upcoming courses and recommendations curated for you.

## Lecture Notes



Download lecture notes and get access to recorded sessions of Live Classes. Revisit important topics whenever you need.

## Anytime/ Anywhere



Watch our Live Classes anytime from anywhere from any of your device.



# ICONIC



# PLUS



## Personal Guidance

Get one on one guidance from top exam experts



## Study Planner



Customized study plan with bi-weekly reviews



Live Classes



Weekly Tests



Structured Courses



Unlimited Access



## Test Analysis

Get one on one guidance from top exam experts



## Experts' Guidelines

Study booster workshops by exam experts

# Unacademy Subscription



## Plus Subscription

× Judiciary - PCS (J) subscription

- ✓ India's best educators
- ✓ Daily interactive live classes
- ✓ Structured courses and PDFs
- ✓ Live Mock Tests & Quizzes

24 months <small>No cost EMI</small>	₹2,635/mo ₹63,250	>
18 months <small>No cost EMI</small>	₹2,965/mo ₹53,367	>
12 months <small>No cost EMI</small>	₹3,624/mo ₹43,484	>
6 months <small>No cost EMI</small>	₹5,271/mo ₹31,625	>

**PPS32**



## Iconic Subscription

× Judiciary - PCS (J) subscription

- ✓ India's best educators
- ✓ Daily interactive live classes
- ✓ Structured courses and PDFs
- ✓ Live Mock Tests & Quizzes

24 months <small>No cost EMI</small>	₹4,360/mo ₹104,650	>
12 months <small>No cost EMI</small>	₹5,349/mo ₹64,185	>
6 months <small>No cost EMI</small>	₹6,996/mo ₹41,975	>

**PPS32**

# BUGS BOUNTY



Opportunity for all Learners to report any inappropriate content in the video

Be the first one to report a particular issue to claim your prize

**Report any inappropriate content using the form in the description**



# Thank You!



+ SUBSCRIBE



Download Now!

